



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 278]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 27, 2003/चैत्र 6, 1925

No. 278]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 27, 2003/CHAITRA 6, 1925

दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2003

का.आ. 330(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 14घ के साथ पठित धारा 14ख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार (दूरसंचार विभाग) की अधिसूचना सं. का.आ. 1346(अ) तारीख 20 दिसम्बर, 2002 को उन बातों के सिवाय, अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) डी.पी. वाधवा को, दूरसंचार विवाद समाधान और अपील अधिकरण के अध्यक्ष के रूप में 1 अप्रैल, 2003 से ही प्रारंभ होने वाली और उस तारीख को, जिसको वह सत्तर वर्ष की आयु पूरी करते हैं अर्थात् 4 मई, 2005 को समाप्त होने वाली और अवधि के लिए नियुक्त करती है।

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2003 को ही प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 15-7/2002-पुनर्गठन]

पी.के. तिवारी, उप सचिव (पुनर्गठन)

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND  
INFORMATION TECHNOLOGY

(Department of Telecommunications)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th March, 2003

S.O. 330(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 14B read with Section 14D of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997) and in supersession of the notification of the Government of India (Department of Telecommunications) number S.O. 1346(E), dated the 20th December, 2002, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby appoints Justice (retired). D.P. Wadhwa, as the Chairperson of the Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal for a further period commencing on and from the 1st April, 2003 and ending with the date on which he attains the age of 70 years i.e. on the 4th May, 2005.

2. This notification shall come into force on and from the 1st April, 2003.

[F. No. 15-7/2002-Restg.]

P. K. TIWARI, Dy. Secy. (Restg.)